आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 22.11.2024
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा– सरकार डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा लाएगी।
- प्रदेश सरकार राशन वितरण प्रणाली में बायोमेट्रिक व्यवस्था को हाईटेक बना रही है।
- ईपीएफओ की सदस्य संख्या में इस वर्ष सितंबर में 18 लाख 81 हजार नए सदस्य जुड़े।
- चमोली जिला प्रशासन ने ज्योर्तिमठ में ग्रीन और येलो श्रेणी के आवासीय भवनों की अस्थाई मरम्मत की अनुमति दी।

डेटा गोपनियता

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश का एक प्रमुख देश बनेगा और कानूनी मज़बूती से डेटा को सुरक्षित रखना संभव होगा।

श्री गोयल ने ब्रिटेन–भारत व्यापार परिषद के सम्मेलन में कहा कि डेटा के लिए काफी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और देश के पावर ग्रिड की इसमें बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल विश्व को टिकाऊ ढांचा दे सकने के मामले में भारत सबसे अच्छी स्थिति में है।

पत्रकार वार्ता

खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि राज्य में राशन वितरण व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राशन वितरण में बायोमेट्रिक व्यवस्था को हाईटेक बना रही है, ताकि सुदूरवर्ती जिलों में भी सिस्टम कारगर हो और प्रदेश की गिनती सौ प्रतिशत ऑनलाइन राशन वितरण करने वाले राज्यों में हो सके। इसके लिए अधिकारियों को 15 दिसंबर तक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्रीमती आर्या ने कहा कि प्रदेश के राशन विक्रेताओं को जून माह तक का लाभांश दे दिया गया है। शेष लाभांश व भाड़े के भुगतान की धनराशि के लिए केंद्र सरकार को जानकारी दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार के स्तर से भी लाभांश भुगतान के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शतप्रतिशत राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं को दुकान खोलने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। साथ ही सशर्त शतप्रतिशत लाभार्थियों को

राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं पर अनावश्यक दबाव न बने, इसके लिए भी आदेश जारी किया जाएगा।

उपचुनाव मतगणना

केदारनाथ विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी, जिसके लिए चाक–चौबंद व्यवस्था की गई है। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कौंडे ने बताया कि ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है, जहां तीन लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम की आईटीबीपी, अर्द्धसैनिक बल और पुलिस के जवान के साथ ही सीसीटीवी से भी कड़ी निगरानी की जा रही है।

मुख्य विकास अधिकारी

देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने डोईवाला विकासखंड के अंतर्गत संचालित उत्तरा एम्पोरियम रानीपोखरी और आईटीडीए ग्रोथ सेंटर ऋषिकेश का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सीएलएफ से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया और वहां प्रदर्शित उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और विपणन प्रक्रिया की सराहना की। महिलाओं ने विपणन और उत्पाद लेबलिंग में आने वाली समस्याओं को साझा किया। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने उनके समाधान के लिए सुझाव मांगे और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक को अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर इन उत्पादों के विपणन को अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए। वहीं, मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रोथ सेंटर ऋषिकेश में स्थापित प्रैक्टिकल लैब का भी निरीक्षण किया और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की। मुख्य विकास अधिकारी ने देहरादून जिले में एक और प्रशिक्षण केंद्र या ग्रोथ सेंटर के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। इससे जिले के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार व आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य बढोतरी

इस वर्ष सितम्बर महीने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुडे सदस्यों में नौ दशमलव तीन तीन प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान 18 लाख 81 हजार नए सदस्य जुड़े हैं। इनमें 59 प्रतिशत हिस्सेदारी 18 से 25 वर्ष के आयु समूह के लोगों की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार, सदस्य संख्या में यह वृद्धि रोजगार के अवसर बढने, कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के प्रति जागरूकता और संगठन की प्रभावी पहल के कारण हुई है। अस्थायी पे–रोल डेटा के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह में कुल नौ लाख 47 हजार नए सदस्यों का पंजीकरण हुआ है। इनमें 18 से 25 आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों के 59 प्रतिशत से भी अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि सितम्बर महीने में लगभग दो लाख 47 हजार महिलाएं संगठन से जुडी हैं।

कर्मचारी भवष्यि निधि

केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि आधार से जुड़ी ओटीपी के जरिए कर्मचारियों का यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर सक्रिय रहे। इसका उद्देश्य अधिकाधिक नियोक्ताओं और कर्मचारियों को इस वर्ष के बजट में घोषित नियोजन आधारित आर्थिक प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाना है।

अनुमति प्रदान

चमोली जिले के ज्योर्तिमठ में ग्रीन और येलो केटेगरी के आवासीय भवनों की अस्थाई मरम्मत की अनुमति प्रदान कर दी गई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने इसके आदेश जारी किए है। ज्योर्तिमठ में अस्थाई मरम्मत की अनुमति इस शर्त और प्रतिबंध के साथ दी गई है कि आवासीय भवन में केवल मरम्मत का कार्य किया जाएगा तथा किसी प्रकार का नवनिर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। भवन स्वामी को इस आशय का शपथ पत्र भी देना होगा।

वर्ष 2023 में ज्योर्तिमठ में हुए भू–धंसाव से आवासीय भवनों पर दरारें आने के कारण भवनों को तकनीकी टीम द्वारा असुरक्षित घोषित किया गया था। इसके बाद उच्च जोखिम क्षेत्र के अन्दर और बाहर कुल एक हजार दो सौ अट्ठाईस भवनों को रेड, ब्लैक, यलो और ग्रीन श्रेणी में रखा गया था। तकनीकी संबंधी विभिन्न कारणों के चलते तहसील स्तर से 217 परिवारों को ही उनके प्रभावित भवनों की पूर्ण धनराशि वितरित की गई है और अधिकांश प्रभावित क्षतिग्रस्त भवनों में रह रहे हैं। इसे देखते हुए इस वर्ष 25 सितंबर को मूल निवासी स्वाभिमान संगठन ज्योतिर्मठ और भू–धसाव प्रभावितों ने बताया था कि नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में निर्माण कार्य बंद है। प्रतिनिधियों ने सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए आंशिक रूप से छत, खिडकी, दरवाजे आदि की मरम्मत किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

राष्ट्रीय खेल

उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तेज कर दी गईं हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य खुद सभी कार्यों पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ऐतिहासिक होगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में अन्य राज्यों के मुकाबले स्थाई खेल सुविधाएं अधिक हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, संसाधनों का निरीक्षण कर चुका है।

आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण

देहरादून नगर निगम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन की ओर से दो दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिले के जल संस्थान, जल निगम, शिक्षा विभाग, कृषि, राजस्व, परिवहन और उद्यान विभाग साहित नगर पालिका व नगर पंचायतों

के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को भूकंप, भूस्खलन या किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यवहारिक जानकारी दी ग्ह्मं